IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

आधुनिक बिहार के उन्नायक: डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह

✍ संतोष कुमार
सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग
एस एन कॉलेज, शाहमल खैरा-देव, रोहतास
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

शोध-सारांश: यूँ तो आधुनिक बिहार के निर्माताओं में बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह का नाम मूर्धन्य है, लेकिन उन्हीं के साथ छाया की तरह राजनीतिक जीवन जीनेवाले बिहार विभूति डॉ अनुग्रह नारायण सिंह ऐतिहासिक विमर्श में हाशिये पर धकेल दिये प्रतीत होते हैं। चंपारण सत्याग्रह के पश्चात असहयोग आंदोलन से स्वतन्त्रता प्राप्ति के दौरान उन्होंने प्रादेशिक और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता से भाग लिया। बिहार भारत के उन राज्यों में अग्रगामी था जहाँ जमींदारी उन्मूलन कानून सबसे पहले पारित किए गए थे। बिहार के सामंती समाज के मद्देनजर यह एक क्रांतिकारी कदम था, लेकिन इस क्रांतिकारी कदम के पीछे तत्कालीन वित्तमंत्री अनुग्रह बाबू का सक्रिय प्राणपन था। उनका मानना था कि बिहार जैसे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े राज्य में जमीन की अहमियत किसी भी अन्य संसाधन से बहुत ज्यादा है। जब तक जमीन पर आधारित व्यवस्था समुचित रूप से दुरुस्त नहीं की जाती है, तब तक आर्थिक-सामाजिक समस्याओं का निराकरण संभव नहीं हो सकता है। अनुग्रह बाबू न केवल सामाजिक और आर्थिक, वरन शैक्षणिक उन्नयन को भी बिहार के भावी विकास की कुंजी मानते थे। वे एक साथ कई मोर्चे पर विकास को गति देने की वकालत करते थे। बिहार सरकार के राजस्व के बेहद सीमित साधन होने के बावजूद वे यथाशीघ्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने पर ज़ोर देते रहे। यह उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था कि 1950 और 1960 के दशक में बिहार ने औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी तेज शुरुआत और प्रगति को सुनिश्चित किया था। बिहार के प्रथम वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने वित्तीय प्रशासन को सर्वाधिक महत्त्व दिया।

कुंजी शब्द: बिहार-विभूति, अनुग्रह नारायण सिंह, औरंगाबाद, वित्त मंत्री, जमींदारी उन्मूलन

शोध प्रविधि

यह शोध आलेख अपनी प्रकृति में ऐतिहासिक है, इसलिए इसमें ऐतिहासिक स्रोतों का उपयोग किया गया है। चूँकि वर्ण्य विषय एक राजनीतिक व्यक्ति और लंबे समय तक बिहार सरकार में वित्त मंत्री रहे, इसलिए उनके जीवन और कार्यों के लिए अभिलेखीय सामग्री का सहारा लिया गया। प्राथमिक स्रोतों के साथ समकालीन व्यक्तियों और परवर्ती लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों और संस्मरणों का भी यथास्थान प्रयोग किया गया है।

प्रारम्भिक जीवन

आधुनिक बिहार के गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले विभूतियों में डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह का नाम अग्रणी है। समर्पित स्वतन्त्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ के साथ-साथ सफल प्रशासक और विधि-निर्माता के रूप में उनकी भूमिका प्रशंसनीय है। 18 जून 1887 को जन्मे अनुग्रह बाबू का सम्बन्ध तत्कालीन गया जिला के औरंगाबाद अनुमंडल के प्रभावशाली जमींदार परिवार से रहा है। इनके वंशज का मूल स्थान आज के उत्तर प्रदेश का मैनपुरी क्षेत्र माना जाता है, जहाँ से वे 18वीं सदी में धार्मिक यात्रा पर काशी के लिए निकले थे और फिर गया की ओर प्रस्थान कर गए। चौहान वंश से सम्बद्ध इनके पूर्वजों ने मार्ग में विश्राम के लिए औरंगाबाद के निकट डेरा डाला। समीप के गाँव के लोगों को बाह्य आक्रांताओं से मुक्ति दिलाने में इनके परिवार के 7 में से 6 भाइयों ने अपनी जान गँवा दीं। इस क्षत्रिय परिवार की वीरता की गाथा सुनकर निकट के माली राज्य के शासक एवं अन्य ग्रामीणों ने वहीं बसने की सलाह दी। यही जगह पोइयावाँ गढ़ कहलाया जो अनुग्रह बाबू की जन्मभूमि है।[1] इनके परिवार के सोमेश्वर राय को प्राप्त 12 गाँवों की जमींदारी का दायित्व परवर्ती काल में

अनुग्रह बाबू को प्राप्त हुए, परंतु वे इन दायित्वों से मुक्त होकर शिक्षा के लिए गाँव से बाहर जाने को तत्पर थे। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में उनका नाम उग्र सिंह था, परंतु उनकी शालीनता एवं उदारता को देखते हुए उनके एक शिक्षक ने उनका नाम बदलकर अनुग्रह रख दिया।[2] प्रारम्भिक शिक्षा में अपने पिता के आदेश के कारण कुछ अड़चनें आयीं, लेकिन उन्होंने आत्म-निर्णय को प्राथमिकता देते हुए स्कूली शिक्षा के लिए औरंगाबाद एवं गया तथा उच्च शिक्षा के लिए पटना एवं कलकत्ता का रूख किया। कलकत्ता में कानून की पढ़ाई के समय उनकी मुलाक़ात डॉ राजेन्द्र प्रसाद से उनके गुरु के रूप में हुई।

राजनीति में प्रवेश

कलकत्ता से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भागलपुर के तेजनरायण जुबली कॉलेज में इतिहास के व्याख्याता के रूप में अपनी सेवा दी। इसके पश्चात वकालत की प्रैक्टिस के लिए पटना आ गये। पटना में प्रैक्टिस के दौरान तीन कठिया प्रणाली से पीड़ित किसानों के बयान लेने के लिए इन्हें चंपारण जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ इन्हें महात्मा गाँधी का सान्निध्य प्राप्त हुआ। इसके बाद लगभग 3 वर्षों (अगस्त 1917 से नवंबर 1920) तक डुमरांव राज के बर्मा केस में वकील के रूप में कार्य किया।[3] डुमरांव राज की सेवा छोड़ने के पश्चात दिसंबर 1920 में नागपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया तथा वहाँ से वापस लौटते ही वकालत छोड़ने का मन बना लिया। इस दौरान स्कूल, कॉलेज एवं वकालत छोड़कर स्वतन्त्रता आंदोलन में शामिल होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की 1920 में विजयवाड़ा में हुई बैठक में निर्धारित कार्यक्रम को पूरा करने के लिए भावी रणनीति तय की गई। इसमें तिलक स्वराज फंड के लिए एक करोड़ रूपये एकत्रित करना, एक करोड़ कांग्रेस सदस्य बनाना तथा 20 लाख चरखों का प्रचार करना सुनिश्चित किया गया। बिहार प्रांत को मात्र 3 महीने में 10 लाख रूपये एकत्रित करने का लक्ष्य दिया गया था।[4] उपर्युक्त परिस्थितियों से प्रभावित एवं प्रेरित होकर 1921 में अनुग्रह बाबू ने श्री ब्रजनंदन प्रसाद एवं श्री रामनवमी प्रसाद के साथ स्वतन्त्रता आंदोलन में सक्रिय होने के लिए अपने-आपको राजेन्द्र बाबू को सुपुर्द कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब कमिटी का चुनाव अस्थायी रूप से हुआ, तब राजेन्द्र बाबू मंत्री बने और अनुग्रह बाबू उनके अधीन सहायक मंत्री हुए। विजयवाड़ा अधिवेशन में निर्धारित राशि के संग्रह के लिए प्रांत के विभिन्न जिलों में लोगों के बीच उत्साह देखने को मिला, परंतु गया जिले के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं थी। अनुग्रह बाबू ने कृष्णवल्लभ बाबू के साथ औरंगाबाद एवं उसके कुछ गाँवों में दौरा कर धनराशि एकत्र की और प्रांतीय लक्ष्य को पूरा किया।[5]

अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 16 अगस्त 1921 को पटना में आयोजित हुई, जिसमें अनुग्रह बाबू ने प्रातीय कांग्रेस समिति के सहायक सचिव के रूप में भाग लिया।[6] असहयोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए तथा खादी की उपयोगिता हेतु लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। 1922 में गया में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें स्वागत समिति का सदस्य चुना गया, जिसमें इनकी भूमिका सराहनीय रही। अक्तूबर 1923 में नए म्युनिसिपल एक्ट के तहत बिहार में नगरपालिकाओं का चुनाव हुआ, जिसमें पटना नगरापालिका के महापौर डॉ राजेन्द्र प्रसाद और उपमहापौर अनुग्रह बाबू निर्वाचित हुए।[7] कुछ दिनों बाद गया जिला बोर्ड के चेयरमैन निर्वाचित होने के बाद अनुग्रह बाबू ने गया में अनेक संरचनात्मक एवं सुधारात्मक कार्य किये। वर्ष 1924 में देश में अनेक स्थानों पर हिन्दू-मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए जिससे बिहार भी अछूता नहीं रहा। गया में हुए दंगों एवं सांप्रदायिक वैमनस्य को दूर करने के लिए इन्होंने दोनों समुदायों के बीच मेल-मिलाप करने का प्रयास किया।

1925 में कौंसिल ऑफ स्टेट का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित उम्मीदवारों में श्री कृष्ण सिंह एवं अनुग्रह बाबू शामिल थे। इसमें अनुग्रह बाबू निर्वाचित हुए, परन्तु दुर्भाग्यवश श्री बाबू को पराजय का सामना करना पड़ा। इस घटना पर कुछ लोगों द्वारा इन दोनों के बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश की गई, परन्तु वे असफल रहे। 8 फरवरी 1926 को अनुग्रह बाबू ने काउंसिल ऑफ स्टेट दिल्ली में शपथ ग्रहण किया एवं उन्होंने सैकरिन पर आयात शुल्क उठाना, पटना उच्च न्यायालाय में मुकदमों का ढेर, कॉमनवेल्थ इंडिया बिल, बिहार-उड़ीसा से कोयला के निर्यात पर टैक्स आदि मुद्दों पर सवाल पूछा।

1928 में जब साइमन कमीशन का बॉम्बे में आगमन हुआ तो पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुए। लाहौर में इस कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लगातार लाठियों से प्रहार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के साथ-साथ भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए गठित इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने से बिहार के लोगों में काफी रोष व्याप्त था। आयोग के पटना आने की तिथि 12 दिसम्बर,1928 निर्धारित की गई एवं इसके पूर्व ही 9 दिसम्बर को कमीशन के बहिष्कार के लिए पटना में एक प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके सभापति अनुग्रह बाबू को और स्वागत समिति का अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया।[8] इस प्रकार "साइमन गो बैक" के नारे पूरे प्रांत में गूंजने लगे एवं विरोध-प्रदर्शन के साथ-साथ लोगों में स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना बलवती होती गयी। 4 मार्च 1929 को महात्मा गाँधी के द्वारा कलकत्ता में विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। इसकी खबर मिलते ही बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष होने के कारण अनुग्रह बाबू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं

से अपील की एवं प्रांत के अनेक गाँवों व शहरों में 17 मार्च 1929 को विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करते हुए इसकी होली भी जलाई गई।[9]

जब गाँधीजी के द्वारा नमक सत्याग्रह की घोषणा की गई, तब बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में नमक आन्दोलन चलाया गया, जिसमें 13000 सत्याग्रही जेल भेजे गये। 16 जनवरी 1931 को पटना के भंवर पोखर में संध्या 5 बजे अनुग्रह बाबू ने झंडोत्तोलन किया और गढ़वाल रेजीमेंट को भारतीयों पर गोली न चलाने की सराहाना की।[10] वर्ष 1931 के प्रारम्भिक दिनों में ही मुंगेर के तारापुर एवं बेगूसराय में झण्डा फहराने के दौरान गोली चलने से अनेक लोग मारे गये। अनुग्रह बाबू ने बेगूसराय की घटना को सर्चलाइट में प्रकाशित करवाया जिसके परिणामस्वरूप जाँच के बाद दोषी पाए गये अवर प्रमंडल पदाधिकारी एवं डीएसपी का तबादला कर दिया गया।[11] 1931 में ही अनुग्रह बाबू को प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 5 मार्च 1931 को हुए गाँधी-इरविन समझौते के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस कार्यकारिणी पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया एवं सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान गिरफ़्तार कांग्रेसी नेताओं को बिना शर्त रिहा किया गया। परन्तु दूसरे गोलमेज़ सम्मेलन की असफलता के कारण कांग्रेस को दुबारा सत्याग्रह शुरू करना पड़ा जिसमें प्रतिक्रियास्वरूप महात्मा गाँधी एवं कांग्रेस कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को गिरफ़्तार किया गया तथा कांग्रेस को गैर-कानूनी घोषित किया गया। 26 जनवरी 1933 को स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर अनुग्रह बाबू को भी गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें एवं चंद्रावती देवी को 15-15 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।[12]

15 जनवरी 1934 को बिहार में आए भूकंप में लगभग बीस हजार से अधिक लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई। उस समय अनुग्रह बाबू हजारीबाग जेल में थे। इनके जेल से रिहा होने के बाद मार्च 1934 में ***बिहार सेंट्रल रिलीफ़ कमिटी*** का गठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनयम-1860 के तहत किया गया, जिसमें डॉ राजेन्द्र प्रसाद को अध्यक्ष, बलदेव सहाय, एम॰एस॰एम हाफ़ीज़ एवं अनुग्रह बाबू को जनरल सेक्रेटरी चुना गया।[13] आगे की बैठक में अनुग्रह बाबू को कमिटी का सचिव नियुक्त किया गया। इन्होंने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए अनेक प्रयास किये तथा आर्थिक मदद के लिए तत्परता दिखाई। वे नवंबर 1934 में केंद्रीय असेंबली के लिए पटना-शाहाबाद क्षेत्र से निर्वाचित हुए तथा बिहार से संबन्धित मुद्दों पर कई सवाल पूछा।

सरकार में शामिल

भारत शासन अधिनियम-1935 के अंतर्गत प्रान्तों में चुनावों की घोषणा की गई। यद्यपि कांग्रेस ने इस अधिनियम को स्वीकार नहीं किया तथापि चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्णय लिया गया। बिहार में 1937 में हुए चुनावों में कांग्रेस की भारी विजय हुई। शुरू में मोहम्मद युनूस सरकार का गठन तो हुआ, लेकिन कांग्रेस के उचित विरोध एवं उसे मिले बहुमत के कारण बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी। गवर्नर के इस आश्वासन पर कि प्रांतीय मंत्रिमंडल की नीति एवं कार्यों में वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, श्री कृष्ण सिंह ने विधायक दल का नेता एवं अनुग्रह बाबू ने वित्त मंत्री एवं स्थानीय स्वशासन मंत्री का पदभार ग्रहण किया। वित्तमंत्री के रूप में अनुग्रह बाबू ने बिहार की आर्थिक उन्नति के लिए कृषि के साथ-साथ कुटीर एवं लघु उद्योग की स्थापना तथा पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य किया। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के लिए पहल जैसे विषयों को प्राथमिकता प्रदान करने के हिमायती थे। कृषि आय पर कर-निर्धारण के मामले में संयम बरतते हुए इसे रैयतों के लिए कल्याणकारी बताया। वहीं जमींदारों को आश्वस्त किया गया कि कर-वसूली में उनके साथ सख्ती नहीं होगी। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये गये।[14]

1939 में दूसरा महायुद्ध शुरू होने पर भारत को इसमें शामिल करने के कारणों की अस्पष्टता के चलते बिहार मंत्रिमंडल ने 31 अक्तूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। 1940 में रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में गाँधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक संघर्ष एवं रचनात्मक कार्य के संचालन पर विशेष ज़ोर दिया गया। इसके लिए सत्याग्रह आश्रम एवं स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण शिविर स्थापित करने की अनुशंसा की गई। 1940 में ही 20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जब डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने सोनपुर में सत्याग्रह शिविर का आयोजन किया, तब उसमें श्री बाबू, अनुग्रह बाबू, जगलाल चौधरी सहित कुल 291 सत्याग्रहियों ने भाग लिया।[15] कांग्रेस कार्यसमिति की 15 सितंबर 1940 को बॉम्बे में आहूत बैठक में गाँधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा के परिणामस्वरूप बिहार में भी 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गया।

श्री कृष्ण सिंह को प्रथम सत्याग्रही के रूप में बांकीपुर से गिरफ्तार किया गया, वहीं अनुग्रह बाबू पटना सिटी में भाषण देने के लिए गिरफ्तार हुए। 26 अगस्त 1941 को अनुग्रह बाबू को जेल से रिहा किया गया।दिसंबर 1941 में पूर्णिया में आयोजित सम्मेलन में अनुग्रह बाबू, जगलाल चौधरी एवं विनोदानंद झा ने भाग लिया जिसमें सत्याग्रह की उपयोगिता एवं रचनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा हुई।[16] 31 जुलाई 1942 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित सभा में अनुग्रह बाबू ने छात्रों से अपील की कि गाँधी जी के इस क्रांतिकारी

कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करें। कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को "भारत छोड़ो प्रस्ताव" पास किया गया एवं गाँधी जी ने जनता के नाम "करो या मरो" का संदेश दिया। 9 अगस्त को डॉ राजेन्द्र प्रसाद, 10 अगस्त को श्री कृष्ण सिंह और 11 अगस्त को अनुग्रह बाबू को गिरफ्तार किया गया।

जून 1944 में जेल से रिहा होने के बाद अनुग्रह बाबू ने समाज सेवा पर बल देते हुए हैजा, मलेरिया एवं कोसी नदी के धारा-परिवर्तन से नुकसान पर निबंध प्रकाशित करवाये। 16 जनवरी 1945 को बिहार रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ जिसमें रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करवाने के लिए एक परामर्शदात्री समिति का गठन हुआ। इसके सदस्य श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, मुरली मनोहर प्रसाद, पंडित प्रजापति मिश्र एवं प्रोफेसर अब्दुल बारी थे। ब्रिटिश सरकार को आशंका हुई कि यह समिति रचनात्मक कार्य के नाम पर राजनीतिक प्रचार करेगी। इसलिए समिति के पांचों सदस्यों पर एक अध्यादेश के तहत गृह नज़रबंदी का आदेश जारी किया गया। इस समय अनुग्रह बाबू बिहार से बाहर सेवाग्राम की यात्रा पर थे। उन्होंने रास्ते में ही नागपुर से बिहार के मुख्य सचिव को तार के माध्यम से उक्त आदेश को तत्काल स्थगित करने का अनुरोध किया। पटना वापस आते ही मुख्य सचिव को उन्होंने स्थिति स्पष्ट की, जिसके उपरांत 13 मार्च 1945 को अनुग्रह बाबू सहित सभी पाँच लोगों पर लगा नज़रबंदी आदेश रद्द कर दिया गया।[17] 1946 के चुनावों में बिहार में 152 सीटों वाली विधान सभा में 98 सीट प्राप्त कर कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। श्री कृष्ण सिंह को प्रधानमंत्री और अनुग्रह बाबू को पुन: वित्त मंत्री बनाया गया। इस कार्यकाल में केंद्र सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता के आधार पर विकास योजनाएँ प्रारम्भ की गईं और किसानों से "*पैडी लेवी ऑर्डर*" के तहत सरकार प्रत्यक्ष रूप से धान का क्रय करने लगी।[18] सरकारी क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 1947 में एक भ्रष्टाचार विरोधी सेल का गठन किया गया। 1947 में पटना विश्वविद्यालय द्वारा श्री बाबू एवं अनुग्रह बाबू को ऑनरेरी डोक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। इसी वर्ष अनुग्रह बाबू ने जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दिसम्बर माह में एक भारतीय खाद्य प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने नेपाल की भी यात्रा की। 1950 में जेनेवा में होनेवाले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी।[19] इस प्रकार इन विदेशी दौरों से प्राप्त प्रशासनिक अनुभव को बिहार के विकास के लिए उपयोग किया गया।

आजादी के बाद नए बिहार के निर्माण में योगदान

15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी का जश्न देश के अन्य क्षेत्रों की तरह बिहार के लोगों ने भी मनाया, परन्तु इसी के साथ प्राप्त देश के विभाजन ने अनुग्रह बाबू को अधिक व्यथित किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के कुछ माह बाद ही महात्मा गाँधी की हत्या ने मानो उन्हें स्तब्ध ही कर दिया, क्योंकि स्वतन्त्रता आंदोलन से लेकर अब तक की प्राशासनिक उपलब्धियों में गाँधी जी के विचारों का उनके जीवन में काफी अधिक महत्त्व था। 1947 में जब कलकत्ता दंगे की प्रतिक्रिया में बिहार के कई इलाकों में दंगे हुए तो गाँधी जी के साथ अनुग्रह बाबू ने कई दंगाग्रस्त इलाकों के दौरे किए थे।

बिहार टेनेन्सी एक्ट 1885 के तहत भूमि के लगान को अन्न से रूपये में परिवर्तित करने हेतु प्रांत के विविध जिलों में 100 से अधिक अधिकारी बहाल किये गये। अनुग्रह बाबू ने स्वास्थ्य, पुलिस, स्थानीय स्वशासन, कृषि, पशुपालन, उद्योग- सहकारिता, विस्थापितों की समस्या तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विकास आदि पर विशेष बल दिया।[20] उन्होंने 1950 में सिंदरी में मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करवायी। स्वतन्त्रता संग्राम में जेल यातना सहनेवालों को 1950 के अंत तक कुल 16.47 लाख रूपये दिये गये।[21] अनुग्रह बाबू जैसे दूरदर्शी व्यक्तित्व के पहल के कारण ही स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गैर-सरकारी कन्या उच्च विद्यालयों को सरकारी अनुदान मिलने लगा तथा बुनियादी शिक्षा को भी बढ़ावा मिला।

1950 के बिहार लैंड रिफ़ोर्म्स एक्ट को भारत के राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने पर अनुग्रह बाबू ने प्रसन्नता जतायी। प्रारम्भ में इसे पटना उच्च न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया गया, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद सरकार की जीत हुई। बिहार की पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) के निर्माता अनुग्रह बाबू ही थे। दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, मोकामा का राजेन्द्र पुल, डेहरी ऑन सोन में सड़क पुल, सामुदायिक विकास योजनाएँ आदि अनुग्रह बाबू के सूझ-बूझ के ही परिणाम थे। इन पर लगभग 125 करोड़ रूपये खर्च हुए। 17 फरवरी 1955 को बिहार विधान-सभा में अनुग्रह बाबू ने गर्व से कहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू करने में 1951 से 1954 तक बिहार ने भारत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया।[22] 1952 में पटना से बाहर के छात्रों को लिए बिहार विश्वविद्यालय एवं कई शोध संस्थानों की स्थापना की गई। 1952 में ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्थापित की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी, डेप्युटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ एजुकेशन आदि पद सृजित किए गये। जून 1954 में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में अनुग्रह बाबू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण सम्मेलन में भाग लेने हेतु कनाडा के टोरंटो शहर की यात्रा की। पलामू भूदान सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इससे एक शांतिपूर्ण क्रांति का सूत्रपात हो रहा है। गया जिले में उन्होंने 8000 एकड़ भूमि दान के रूप में प्राप्त किया।

1953-54 में उन्होंने अधिक अन्न उपजाओ अभियान, समुदाय प्रोजेक्ट, भ्रष्टाचार उन्मूलन, बंजर भूमि को आबाद करने, भूमि सर्वे और सेटलमेंट आदि पर विशेष ध्यान दिया। 1954-55 के बजट में किसानों को ऋण वितरित करने, कोसी योजना को क्रियान्वित करने, पथ एवं भवन-निर्माण, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा आदि को प्राथमिकाता प्रदान की गयी।1955-56 में बाढ़ और सूखा से राहत के लिए अनुग्रह बाबू ने 9.39 लाख रूपये खर्च किए।[23] 1956-57 में बाढ़ राहत के लिए विशेष प्रावधान करना पड़ा क्योंकि दक्षिण बिहार विशेषकर छोटानागपुर में बाढ़ का काफी प्रकोप रहा। इस वर्ष 7.42 लाख रूपये का प्रावधान किया गया, जिसमें 4.42 लाख किसानों को कर्ज के रूप में देने थे।[24]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में भी अनुग्रह बाबू ने बड़ी भूमिका निभाई। इस योजना में कोसी तथा दूसरी नदियों के बाढ़ को रोकने के लिए 31.5 करोड़ रूपये खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 1956-57 के बजट में उन्होंने अकाल के लिए 50 लाख और किसानों को ऋण देने के लिए 60 लाख का प्रबंध किया। 1955-56 के बजट पर बहस के दौरान अनुग्रह बाबू ने सदन में कहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों के हिसाब से बिहार देश के पाँच उत्कृष्ट प्रांतों में से था।[25] अप्रैल 1956 तक अनुग्रह बाबू ने कांके, पूसा, गया, दुमका आदि जगहों पर कृषि विद्यालयों की स्थापना करवायी। दो बुनियादी कृषि विद्यालयों की शाखा पटना और मुजफ्फरपुर में विस्तार शिक्षा केन्द्रों के साथ संचालित किए गये।

वर्ष 1957 में वे काफी बीमार हो गये और 28 जून 1957 को पटना जनरल अस्पताल के कॉटेज में भर्ती हुए। 3 जुलाई को दिल्ली से डॉ राजेन्द्र प्रसाद उनसे मिलने आए एवं उसके दो दिनों के बाद 5 जुलाई 1957 को गुर्दे की बीमारी के कारण इनका निधन हो गया।[26] आधुनिक बिहार के इस महान पथ-प्रदर्शक की स्मृति में पटना में अनुग्रह नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज की स्थापना हुई जिसका उद्घाटन 1959 में भारत के राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद के कर-कमलों द्वारा किया गया। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि डॉ अनुग्रह नारायण सिंह जैसे आधुनिक बिहार के निर्माता के नेतृत्व में 1946 से 1956 के दशक में बिहार में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई। उन्होंने लगभग 13 वर्षों तक बिहार प्रांत के विधायक एवं वित्त मंत्री के रूप में अप्रतिम प्रशासनिक क्षमता तथा अदम्य साहस का परिचय दिया। श्रीकृष्ण सिंह ने भी स्वीकार किया, "*बिहार सरकार में अनुग्रह बाबू का स्थान यह है कि यदि उन्हें वहाँ से हटा दिया जाय तो मैं शासन नहीं चला सकता।*"[27] स्पष्ट है उनकी भूमिका को उनके समकालीनों ने भी सहज ही स्वीकार किया है।

संदर्भ:

[1] मिश्रा, आर (2015): "अनुग्रह नारायण सिन्हा: द मैन एंड हिज मिल्यू",अभिलेख बिहार, अंक-8, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ- 313-14

[2] झा, जे सी (19889: "बिहार-विभूति: डॉ अनुग्रह नारायण सिंह- एक जीवनी", बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, पृष्ठ-10

[3] सिंह, ए .एन. (2012): "मेरे संस्मरण", बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना द्वारा प्रकाशित (चतुर्थ संस्करण), पृष्ठ- 19

[4] वही,पृष्ठ-35

[5] वही, पृष्ठ-37

[6] कुमार, विजय (2017): रेकॉर्ड्स ऑफ द विजिट ऑफ महात्मा गाँधी इन बिहार इन डिफरेंट फेजेज़, 1920-47" डायरेक्टोरेट ऑफ बिहार स्टेट आर्काइव्स, वॉल्यूम-1, पृष्ठ-175

[7] कुमार, विजय (2017): "रेकॉर्ड्स ऑफ द विजिट ऑफ महात्मा गाँधी इन बिहार इन डिफरेंट फेजेज़, 1920-47" वॉल्यूम-1,डायरेक्टोरेट ऑफ बिहार स्टेट आर्काइव्स, पृष्ठ-175

[8] दत्त, के.के.(1974): " बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास", बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी,पटना, प्रथम संस्करण, भाग-1, पृष्ठ-467

[9] तिवारी, पी. एन. (2013): "बिहार-विभूति डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह", बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ -54

[10] वही, पृष्ठ-60

[11] दत्त, के.के.(2016): "गाँधीजी इन बिहार", डायरेक्टोरेट ऑफ बिहार स्टेट आर्काइव्स, पटना,सेकेंड एडीशन, पृष्ठ- 164

[12] तिवारी, पी. एन. (2013): "बिहार-विभूति डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह", बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ-60

[13] वही, पृष्ठ-61

[14] तिवारी, पी. एन. (2013): "बिहार-विभूति डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह", बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ-82-84

[15] अभिलेख बिहार, डायरेक्टोरेट ऑफ बिहार स्टेट आर्काइव्स, पटना द्वारा प्रकाशित, अंक-06,पृष्ठ-91

[16] अभिलेख बिहार, डायरेक्टोरेट ऑफ बिहार स्टेट आर्काइव्स, पटना द्वारा प्रकाशित, अंक-05,पृष्ठ-161

[17] दत्त, के.के.(2014): " बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास", बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी,पटना, तृतीय संस्करण, भाग-3, पृष्ठ-302

[18] झा, जे सी (1989), पृष्ठ-82

[19] वही, पृष्ठ-85

[20] वही, पृष्ठ-88

[21] वही, पृष्ठ-89

[22] वही, पृष्ठ-94-95

[23] वही, पृष्ठ-105

[24] वही, पृष्ठ-106

[25] वही, पृष्ठ-110

[26] वही, पृष्ठ-117

[27] कुमार, विजय (2013): "अनुग्रह नारायण सिंह स्मृति ग्रंथ: विचार और दर्शन", बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ-99